झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
डब्ल्यूपी (एस) संख्या 103/2016

चंद्र शेखर प्रसाद सिंह, पिताजी स्व. राम आशिर्वाद सिंह, निवासी पी.पी. कंपाउंड, डाकघर और थाना--हिंदपिरी, जिला रांची (झारखंड)।

... ... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, रांची, जिसका अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक उर्जा विकास निगम लिमिटेड, इंजीनियरिंग भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, रांची (झारखंड), पिन कोड-834004.
2. प्रबंध निदेशक, उर्जा वितरण निगम लिमिटेड, इंजीनियरिंग भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, रांची (झारखंड)।
3. निदेशक व्यक्तिगत झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, रांची। (वर्तमान में सामान्य प्रबंधक व्यक्तिगत उर्जा वितरण निगम लिमिटेड, इंजीनियरिंग भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, रांची (झारखंड)।
4. उप निदेशक व्यक्तिगत झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, रांची (वर्तमान में उप सामान्य प्रबंधक व्यक्तिगत उर्जा वितरण निगम लिमिटेड, इंजीनियरिंग भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, रांची (झारखंड)।

.... प्रतिवादी

सन्मुख: सम्मानीय श्रीमान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सुनील कुमार, अधिवक्ता
श्री राम प्रवीश प्रजापति, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से : श्री ओम प्रकाश तिवारी, अधिवक्ता

12/दिनांक: 17 फरवरी, 2024

1. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें 31.07.2009 के दंड आदेश को चुनौती दी गई है और यह प्रार्थना की गई है कि एक वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के कारण जो बकाया राशि रोकी गई थी, उसे वितरित किया जाए।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि रिट याचिका में की गई दलीलों के अनुसार उल्लेख करना आवश्यक है, इस प्रकार हैं:

याचिकाकर्ता 31.05.2014 को मीटर रीडर के पद से सेवानिवृत्त हुए, उस समय वह इलेक्ट्रिक सप्लाई रांची में कार्यरत थे।

उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही आदेश संख्या 694 दिनांक 19.04.2008 के तहत प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता पर कुल 3 आरोप लगाए गए थे। एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना जवाब प्रस्तुत किया और सभी संबंधित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए।

जांच अधिकारी ने सभी संबंधित बिंदुओं और दस्तावेजों की जांच के बाद याचिकाकर्ता को तीनों आरोपों से मुक्त कर दिया, जैसा कि उनके द्वारा 22.07.2008 को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट है।

इसके बाद, विभागीय अधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष से असहमत होकर याचिकाकर्ता पर तीन दंड लगाए। पहला, एक वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश, दूसरा, भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी और तीसरा, निलंबन अवधि के दौरान केवल मूल भत्ते देने का आदेश, जैसा कि आदेश संख्या 1312 दिनांक 31.07.2009 में स्पष्ट है।

याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के अनुपालन में दूसरा कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के बाद विभागीय अधिकारी ने अंतिम आदेश जारी किया और उक्त दंड की पुष्टि की, जैसा कि आदेश संख्या 1312 दिनांक 31.07.2009 में स्पष्ट है, जिसमें विभागीय अधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष से असहमत होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ 31.07.2009 को अपील दायर की थी, जो अभी तक लंबित है, हालांकि समय-समय पर उन्होंने सक्षम प्राधिकरण से संपर्क किया और प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किया।

3. तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो रांची विद्युत आपूर्ति विभाग में मीटर रीडर के रूप में कार्यरत थे, पर कुछ अनियमितताओं के लिए विभागीय कार्यवाही की गई। आरोप पत्र जारी किया गया, जिसके बाद जांच अधिकारी नियुक्त किए गए और याचिकाकर्ता को जांच कार्यवाही में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता जांच कार्यवाही में उपस्थित हुए और आरोप का बचाव किया। जांच अधिकारी ने पाया कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि, विभागीय अधिकारी ने 31.07.2009 के आदेश में जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए स्वयं आरोप को सिद्ध किया और आरोपों के सिद्ध न होने के बावजूद अपने निष्कर्ष में अंतर दिखाया।

विभागीय प्राधिकारी ने निम्नलिखित दंड पारित किए:

1. श्री सिंह की एक वासषिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

2. श्री सिंह को भसवष्य में सचेष्ठ रहने की चेतावनी दी जाती है।

3. श्री सिंह को सनलिंबन अवसि मेंजीवन यापन भत्ता के असतररक्त कुछ भी देय नही होगा, परन्तुसनलिंबन अवसि की गणना सिर्फ़ सेवोत्तर लाभों के लिए की जाएगी।

4. दंड क्रमांक (1) और (3) को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि ये आर्थिक राहत से संबंधित हैं, लेकिन दंड क्रमांक (2) का कोई प्रभाव नहीं रह गया है क्योंकि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
5. श्री सुनील कुमार, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि जब जांच अधिकारी ने यह पाया कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो विभागीय अधिकारी का यह कार्य कि वह अपने विचारों को प्रस्तुत करे और आरोपी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपने निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करे, यह कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। यही काम विभागीय अधिकारी ने किया है, इसलिए यह आदेश कानून की दृष्टि से स्थिर नहीं हो सकता।

6. दूसरी ओर, श्री ओम प्रकाश तिवारी, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने इस आदेश का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि विभागीय अधिकारी ने आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी के निष्कर्ष को अस्वीकार किया और आरोप को सिद्ध पाया, इस आधार पर दंड का आदेश दिया गया।
7. इस न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और याचिका तथा काउंटर हलफनामे की जांच की।

8. दंड आदेश दिनांक 31.07.2009 की वैधता और उचितता चुनौती दी गई है, यह तर्क देते हुए कि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिसमें जांच अधिकारी ने आरोप को सिद्ध न होने की बात कही हो।
9. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क की जांच करने का निर्णय लिया है, जो कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष और विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर आधारित है।
10. यह जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि कुल मिलाकर तीन आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारी के पास भेजी गई थी। विभागीय अधिकारी ने दंडादेश पारित करते समय जांच अधिकारी द्वारा आरोपों को सिद्ध न होने के निष्कर्ष से असहमत होते हुए, 31.07.2009 के आदेश द्वारा दंड लागू किया।
11. यह स्थापित स्थिति है कि जब विभागीय कार्यवाही की बात होती है, तो दो प्रमुख पहलुओं पर विचार किया जाता है, यानी, उस स्थिति में जब आरोप सिद्ध हो गए हैं तो विभागीय अधिकारी को क्या कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, विभागीय अधिकारी जो जांच अधिकारी नहीं होते, उन्हें दंड लागू करना होता है, और जांच रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद, कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक होता है।

लेकिन, यदि जांच अधिकारी और विभागीय अधिकारी एक ही व्यक्ति हैं, तो दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने का उद्देश्य यह होता है कि जब विभागीय अधिकारी अपने मन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर लगाए, तो उसे कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वह यह निष्कर्ष निकाल सके कि उसे कौन सा दंड लगाया जाए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जा सके।

एक अलग स्थिति में, जब जांच अधिकारी ने आरोप को सिद्ध न होने की बात कही हो, तो भी जांच रिपोर्ट विभागीय अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसके बावजूद, विभागीय अधिकारी को दंड लगाने का अधिकार होता है, लेकिन आवश्यक है कि वह अपनी राय में भिन्नता के बारे में कर्मचारी को सूचित करें और उसे जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दें।

12. इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र भी यहाँ उल्लेखनीय है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***भारत संघ बनाम पी. गुणसेकरन, एआईआर 2015 एससी 545,*** में स्पष्ट रूप से स्थापित किया है, विशेष रूप से पैराग्राफ 13 में, जिसमें निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए हैं जो स्व-स्पष्ट हैं:

> *"13. यद्यपि यह एक स्थापित स्थिति है, यह ध्यान में रखते हुए दुखद रूप से यह देखना पड़ता है कि उच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया है, यहां तक कि जांच अधिकारी के सामने सबूतों की पुनः मूल्यांकन भी किया। आरोप संख्या 1 पर पाया गया निष्कर्ष विभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और इसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी अनुमोदित किया था। विभागीय कार्यवाही में उच्च न्यायालय न तो और न ही कार्यवाही की दूसरी अपील अदालत के रूप में कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 226/227 के तहत, सबूतों का पुनः मूल्यांकन नहीं करेगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:*
>
> *a. क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है;*
>
> *b. क्या जांच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;*
>
> *c. क्या कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है;*
>
> *d. क्या प्राधिकरणों ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों से परे किसी अन्य कारणों से निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने में अपनी क्षमता को हानि पहुँचाई है;*
>
> *e. क्या प्राधिकरणों ने अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होकर निर्णय लिया है;*
>
> *f. क्या निष्कर्ष अपने आप में इतना निराधार और मनमाना है कि कोई भी तार्किक व्यक्ति कभी भी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता;*
>
> *g. क्या विभागीय अधिकारी ने स्वीकृत और महत्वपूर्ण प्रमाण को स्वीकार करने में गलती की है;*

h. क्या विभागीय अधिकारी ने अस्वीकार्य प्रमाण स्वीकार किए हैं जिन्होंने निष्कर्ष को प्रभावित किया;

i. क्या तथ्यों का निष्कर्ष बिना किसी प्रमाण के आधारित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च न्यायालय:

(i) सबूतों का पुनः मूल्यांकन नहीं करेगा;

(ii) कार्यवाही में कानूनी रूप से अनुमोदित निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यदि वह कानून के अनुसार की गई हो;

(iii) सबूतों की पर्याप्तता में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(iv) सबूतों की विश्वसनीयता में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(v) यदि कुछ कानूनी साक्ष्य है जिस पर निष्कर्ष आधारित हो सकता है, तो हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(vi) तथ्यों की गलती को सुधारने में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो;

(vii) दंड की अनुपातिकता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक वह न्यायालय की अंतरात्मा को आहत न करता हो।"

मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने ***भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन बनाम स्मिता शारद देशमुख और अन्य., (2017) 4 एससीसी 75*** में यह स्पष्ट किया है कि यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दंडात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप दिए गए दंड के परिमाण में हस्तक्षेप कर सकता है, यदि यह अपराध की गंभीरता के अनुपात में अनुपयुक्त पाया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने ***केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य बनाम अबरार अली, एआईआर (2017) एससी 200***, में दंडात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप लगाए गए दंड में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से उद्धृत किए गए हैं:

*"**8**. अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्षों के विपरीत, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के संस्करण को स्वीकार किया कि वह बीमार था और एक स्थानीय डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा था, बिना कोई कारण दिए। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने यह माना था*

कि यूनिट में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं, जिन्हें प्रतिवादी ने यदि वह वास्तव में बीमार था, तो इस्तेमाल किया हो सकता था। इसके अतिरिक्त यह माना गया कि दोषी ने स्थानीय डॉक्टर द्वारा इलाज करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। उच्च न्यायालय को तथ्यों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, जो कि साक्ष्यों की पुनःमूल्यांकन के बराबर है। यह स्थापित कानून है कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को साक्ष्यों की पुनःमूल्यांकन की अनुमति नहीं है।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम नेमी चंद नलवैया, (2011) 4 एससीसी 584 : (एआईआर 2011 एससी 1931, पैरा 6) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"7. यह अब स्पष्ट रूप से स्थापित है कि न्यायालय घरेलू जांच में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के रूप में अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेंगे, न ही साक्ष्य के आधार पर यह कहने के आधार पर हस्तक्षेप करेंगे कि रिकार्ड पर अन्य दृष्टिकोण संभव है। यदि जांच उचित रूप से की गई है और निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित हैं, तो साक्ष्यों की पर्याप्तता या विश्वसनीयता के आधार पर निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होगा। इसलिए, न्यायालय घरेलू जांचों में रिकॉर्ड किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि उन निष्कर्षों का कोई साक्ष्य नहीं हो या वे स्पष्ट रूप से अव्याख्येय हों। अव्याख्येयता का परीक्षण यह देखना होगा कि क्या एक न्यायाधिकरण उचित रूप से ऐसा निष्कर्ष या निर्णय ले सकता था, जो रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हो। हालांकि, न्यायालय अनुशासनात्मक मामलों में निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेंगे, यदि प्राकृतिक न्याय या वैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ हो या यदि आदेश दमनात्मक, मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों पर आधारित हो।"*

भारत संघ और अन्य बनाम पी. गुनेशकरन, (2015) 2 SCC 610 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए:

> *"12. यह स्पष्ट रूप से स्थापित होने के बावजूद कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यह चिंताजनक है कि उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया। अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आरोप-1 पर दिए गए निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया गया था और इसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा भी समर्थन मिला। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय "प्रथम अपील के दूसरे न्यायालय" के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:*

a) जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी;

b) जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी;

c) कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ या नहीं;

d) प्राधिकरण ने साक्ष्यों और मामले के गुणों से अलग किसी अन्य विचारों के कारण उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में स्वयं को अक्षम कर लिया हो;

e) प्राधिकरण ने अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होकर निर्णय लिया हो;

f) निष्कर्ष, सतह पर, इतने मनमाने और कपटपूर्ण हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था;

g) अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने स्वीकार्य और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को गलत तरीके से नजरअंदाज किया हो;

h) अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अस्वीकार्य साक्ष्यों को स्वीकार किया हो, जिससे निष्कर्ष प्रभावित हुआ हो;

i) तथ्यात्मक निष्कर्ष बिना साक्ष्य के आधारित हो।

13. अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च न्यायालय निम्नलिखित नहीं करेगा:

(i) साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन;

(ii) जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप, यदि वह कानून के अनुसार की गई हो;

(iii) साक्ष्यों की पर्याप्तता पर विचार;

(iv) साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर विचार;

(v) यदि वैध साक्ष्य हैं, जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(vi) तथ्यात्मक त्रुटि को ठीक नहीं करेगा, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो;

(vii) दंड की अनुपातिकता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर न दे।

13. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कानून अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है और दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।

14. वर्तमान मामला उस तथ्य से संबंधित है जिसमें जांच के दौरान आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति जताई लेकिन किसी कारण को स्पष्ट किए बिना और आरोपित व्यक्ति को इस असहमति के संबंध में अवसर प्रदान किए बिना अंतिम निर्णय लिया। इस संदर्भ में, कानून ***पंजाब नेशनल बैंक व अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा, (1998)***

7 एस सी सी 84 मामले में स्पष्ट किया गया है। इस मामले में, पैराग्राफ-18 में यह कहा गया है:

> *"**18.** विनियम 6 के तहत, जांच की कार्यवाही या तो किसी जांच अधिकारी द्वारा या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वयं की जा सकती है। जब जांच अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट अंतिम या निर्णायक नहीं होती और अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त नहीं मानी जाती। अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय के साथ समाप्त होती है। केवल अनुशासनात्मक प्राधिकारी ही दंड निर्धारित कर सकता है, जांच अधिकारी नहीं। जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है, वहां उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होता है और भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है, तो इस स्थिति में आरोपित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान न करना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। यह अत्यधिक अनुचित होगा कि जहां जांच अधिकारी के समक्ष आरोपित व्यक्ति सफल होता है, उसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर न दिया जाए, जब वह जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति जताकर, आरोपित को दोषी ठहराने और दंड देने का निर्णय लेता है। हमारे विचार में, ऐसे किसी भी मामले में, अंतिम निर्णय और दंड देने से पहले, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आरोपित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए। यह करुणाकर मामले [(1993) 4 एससीसी 727 : 1993 एससीसी (एल एंड एस) 1184 : (1993) 25 एटीसी 704] में स्पष्ट की गई जांच की पहली अवस्था का हिस्सा है।"*

15. इस न्यायालय ने अब पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू की है और इस उद्देश्य से दंड के अंतिम आदेश को जांच रिपोर्ट के साथ जांचा गया है। चूंकि जांच अधिकारी ने आरोप को सिद्ध नहीं पाया, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उपरोक्त निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया, फिर भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उपलब्ध प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आरोपित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था। यह अवसर प्रदान करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जांच अधिकारी ने आरोप को सिद्ध नहीं पाया था। चूंकि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता पर दंड लगाने की प्रक्रिया स्थापित विधि के अनुरूप नहीं है।
16. जहां तक दंड संख्या (iii) का सवाल है, जिसमें निलंबन अवधि के लिए निर्वाह भत्ता छोड़कर अन्य सभी मौद्रिक अधिकारों को अस्वीकार कर दिया गया है, यह आदेश 31.07.2009 के आदेश संख्या 1312 से स्पष्ट होता है।

17. उक्त दंड सिविल सेवा वर्गीकरण, अपील और नियंत्रण नियम, 1930 के तहत सूचीबद्ध दंडों में उपलब्ध नहीं है, जैसा कि नियम 49 और उसमें सूचीबद्ध दंडों से स्पष्ट होता है।

18. यह विधि द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई दंड सूचीबद्ध दंडों के विपरीत लगाया जाता है, तो उसे अधिकार क्षेत्र के बाहर माना जाएगा। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012) 5 एस सी सी 242*** में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। इस मामले में, जहां लगाए गए दंड को निर्धारित वैधानिक नियमों के तहत नहीं पाया गया, उसे अधिकार क्षेत्र के बाहर माना गया, जैसा कि पैराग्राफ 11 से 15 और 23 में स्पष्ट किया गया है। इन पैराग्राफों का विवरण इस प्रकार है:

> ***"11.*** *यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता पर लगाया गया दंड 1991 के नियम 4 के तहत प्रदान नहीं किया गया है। एक व्यक्ति की ईमानदारी का प्रमाण पत्र उसके वार्षिक गोपनीय आख्या (Annual Confidential Report) भरते समय उचित कारणों से रोका जा सकता है। हालांकि, यदि वैधानिक नियम ऐसा प्रावधान करते हैं, तो इसे एक दंड के रूप में भी रोका जा सकता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कदाचार के लिए दंड स्वरूप ईमानदारी प्रमाण पत्र रोकने का आदेश, नियम 1991 के तहत नहीं होने के कारण, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह नियमों के तहत दंड नहीं कहा जा सकता। नियम अनुशासनात्मक प्राधिकारी को "कोई अन्य" प्रमुख या लघु दंड लगाने का अधिकार नहीं देते। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता जो नियमों के तहत निर्दिष्ट न हो।*
>
> ***12.*** *इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम माधव प्रसाद शर्मा [(2011) 2 एस सी सी 212] में 1991 के नियमों पर विचार किया और नियम 4 का उद्धरण देते हुए यह निष्कर्ष निकाला:*
>
> > *"**16.** हमें अन्य नियमों की चिंता नहीं है। उपरोक्त नियम में उल्लिखित प्रमुख और लघु दंडों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बिना वेतन अवकाश स्वीकृत करना निर्धारित दंडों में से एक नहीं है। हालांकि, किन परिस्थितियों में बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया गया है, यह एक भिन्न विषय है जिससे हम फिलहाल संबद्ध नहीं हैं। परंतु, नियम 4 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि बिना वेतन अवकाश स्वीकृत करना निर्धारित दंडों में से एक नहीं है।विभागीय प्राधिकारी उन दंडों में से उपयुक्त दंड लगाने के लिए अधिकृत है, जो नियम 4 में उल्लिखित प्रमुख और लघु दंडों के रूप में निर्धारित हैं। "कार्य नहीं, वेतन नहीं" के आधार पर वेतन न देना, दंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि नियम 4 में दंडों की स्पष्ट परिभाषा दी गई है।" (प्रमुख बल दिया गया) "*

13. प्राधिकारी को किसी भी विधि या वैधानिक नियम के निष्पादन या उनके प्रयोजन में कार्य करना चाहिए।

14. इस मामले की जांच एक अन्य दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिए। विभागीय कार्यवाही करना, किसी अधिकारी की दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकालना, और उसके लिए दंड देना एक अर्ध-न्यायिक कार्य है, न कि प्रशासनिक कार्य।

15. किसी दोषसिद्धि के लिए दंड लगाना वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित और नियंत्रित होता है। इसलिए, अर्ध-न्यायिक कार्य करते समय, प्राधिकारी उन वैधानिक नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता जिसके तहत दंड लगाया जाना है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी इन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, वैधानिक नियमों के दायरे से बाहर का दंड आदेश शून्य है और याचिकाकर्ता पर लागू नहीं किया जा सकता।

23. उपरोक्त के दृष्टिगत, दंड आदेश विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है। परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। 08.07.2010 का विवादित आदेश, जिसके तहत 2010 का ईमानदारी प्रमाण पत्र रोका गया, और इसके संबंध में सभी अन्य आदेशों को रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के सभी परिणामी लाभ, जिसमें पदोन्नति आदि शामिल हो सकती है, को सेवा रिकॉर्ड के अनुसार पुनः विचार करें और विधि के अनुसार निर्णय लें।

19. उपर्युक्त आदेश को भी वैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेवा संहिता के नियम 97 में निलंबित कर्मचारी के संदर्भ में विशेष प्रावधान किया गया है, जो निष्कलंक प्रमाणित होने पर सेवा में पुनःस्थापित होता है। इस प्रावधान के अनुसार, निलंबन की अवधि के वेतन के अधिकार को समाप्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य है। इस विषय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***श्री महावीर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य, 1988 पीएलजेआर 82*** के निर्णय में संबोधित किया है, जिसमें पैराग्राफ-3 में यह कहा गया है:

"3. श्री तारकेश्वर दयाल, जो याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने प्रतिकूल टिप्पणी (सेंसर) के आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दी। हालांकि, उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश, जिसमें निलंबन की अवधि को पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए सेवा काल माना गया, लेकिन याचिकाकर्ता को निलंबन की अवधि के दौरान प्राप्त निर्वाह भत्ते से अधिक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, यह आदेश अवैध है क्योंकि इसे पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था। इस तर्क के समर्थन में, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय M. गोपालकृष्ण नायडू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर

1968 एससी 240) का हवाला दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संबंधित अधिकारी को विभागीय जांच के दौरान निलंबित किया गया था। जांच अधिकारी ने उसे दोषमुक्त पाया, लेकिन सरकार ने इस निष्कर्ष से असहमति जताई और कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों उसे सेवा से बर्खास्त न किया जाए। बाद में सरकार ने यह माना कि अधिकारी के विरुद्ध आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए हैं। सरकार ने आगे यह भी माना कि निलंबन और विभागीय जांच पूरी तरह अनुचित नहीं थी और आदेश दिया कि अधिकारी की अनुपस्थिति की संपूर्ण अवधि को मूल नियम 54(5) के तहत केवल पेंशन प्रयोजन के लिए सेवा काल माना जाएगा, लेकिन उसे उस अवधि के लिए केवल निर्वाह भत्ता ही मिलेगा, उससे अधिक कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह माना कि मूल नियम 54 यह अपेक्षा करता है कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किया जाए। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी को अधिकारी को यह अवसर देना आवश्यक था कि वह यह स्पष्ट कर सके कि नियम 54(3) और 54(5) को उस पर क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि इस मामले में अधिकारी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अवैध करार दिया। बिहार सेवा संहिता, 1952 का नियम 97, मूल नियम 54 के समान ही प्रावधान करता है। अतः याचिकाकर्ता को यह अवसर दिया जाना चाहिए था कि वह यह स्पष्ट कर सके कि उसके मामले में नियम 97(3) और 97(5) को क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि यह अवसर नहीं दिया गया, याचिका स्वीकार की जाती है, और आदेश के उस भाग को, जिसमें कहा गया है कि "निलंबन की अवधि को पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए सेवा काल माना जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता को केवल निर्वाह भत्ता ही प्राप्त होगा, उससे अधिक कुछ नहीं," अवैध ठहराते हुए रद्द किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी इस विषय पर पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह याचिकाकर्ता को उचित अवसर प्रदान करे ताकि वह प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपना पक्ष रख सके। इस मामले में किसी भी पक्ष को लागत प्रदान नहीं की जाएगी।

इसके पश्चात्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विषय पर विचार किया है ***झारखण्ड राज्य बनाम अमरेश नारायण सिंह, (2020) 14 एससीसी 411*** के मामले में, जहाँ पैराग्राफ-7 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

"7. नियम 97 के उप-नियम (1) के अनुसार, जब किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, तो पुनःस्थापन का आदेश देने वाली प्राधिकरण को यह विचार करना होगा और एक विशिष्ट आदेश पारित करना होगा कि निलंबन की अवधि के दौरान वेतन और भत्तों का क्या होगा और क्या इसे ड्यूटी की अवधि के रूप में माना जाएगा। उप-नियम (2) के अनुसार, यदि प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि निलंबन 'पूरी तरह से अनुचित' था, तो सरकारी कर्मचारी को पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, जैसे निलंबन का आदेश कभी पारित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने नियम 97 के प्रावधानों को गलत तरीके से व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि निलंबन रद्द होने पर

पूर्ण वेतन और भत्ते स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। यह व्याख्या नियम 97 की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है। विभागीय कार्यवाही को आपराधिक मुकदमे की समाप्ति तक स्थगित रखा गया है। केवल विभागीय जांच समाप्त होने के बाद ही प्राधिकारी को नियम 97 के अनुसार यह तय करना होगा कि निलंबन की अवधि को ड्यूटी की अवधि के रूप में माना जाए या नहीं और वेतन और भत्तों के संबंध में क्या निर्णय लिया जाए। उच्च न्यायालय द्वारा इस स्तर पर जारी निर्देश नियम 97 के विपरीत थे।"

20. इस न्यायालय की राय में, उपर्युक्त आधार पर दी गई **दंड संख्या (iii)** कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।
21. एक मुद्दा यह है कि क्या केवल तकनीकी आधार पर किसी लोक सेवक को लाभ दिया जा सकता है।
22. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी केवल तकनीकी आधार पर लाभ नहीं उठा सकता, लेकिन यह सिद्धांत तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए।
23. इस मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता **31.08.2014** को सेवानिवृत्त हो गया और तब से लगभग साढ़े सात वर्ष बीत चुके हैं, जबकि यह कार्यवाही **19.04.2008** को शुरू हुई थी।
24. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 19.04.2008 से विभागीय कार्यवाही का सामना किया और अंतिम दंडादेश 31.07.2009 को पारित किया गया। ऐसे में, यह न्यायोचित और उचित नहीं होगा कि मामले को प्राधिकरण के समक्ष पुनः विचारार्थ भेजा जाए, ताकि उसी आधार पर नई कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। ठीक इसी विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा*** (उल्लेखित) के निर्णय के पैराग्राफ-21 में विचार किया है, जिसमें यह ध्यान रखा गया कि यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के कारण उसे विभागीय कार्यवाही के कठोर प्रभावों का सामना करने के लिए क्यों बाध्य किया जाए। उक्त निर्णय का पैराग्राफ-21 इस प्रकार है:

"21. दोनों प्रतिवादी 31-12-1983 को सेवानिवृत्त हुए। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, मिश्रा का 6-1-1995 को निधन हो गया और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 14 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है जब से दोषी अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। अतः, न्याय के हित में यह उचित नहीं होगा कि इस चरण पर मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास पुनः आरंभ के लिए भेजा जाए। इसलिए, हम इस प्रकार का कोई निर्देश जारी नहीं करते हैं। इन अपीलों को खारिज करते हुए, हम उच्च न्यायालय के निर्णयों को कायम रखते हैं, जिन्होंने दंड लगाने के आदेशों को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को प्रतिवादियों को उनकी

सेवानिवृत्ति के लाभ जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, किसी भी पक्ष को लागत का आदेश नहीं दिया जाएगा।

25. इस न्यायालय की राय है कि उपरोक्त सिद्धांत को इस मामले में भी लागू करते हुए, जब कानून पहले से ही स्थापित है, तो यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कर्तव्य था कि वह वैधानिक प्रावधानों या स्थिर विधि का पालन करे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनकी गलती के कारण दोषी कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही के बोझ का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, विशेषकर नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने के लिए।
26. अतः, इस न्यायालय की राय में, यह मामला ऐसा नहीं है जहां इसे फिर से कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रेषित किया जाए।
27. इस न्यायालय का यह मत है कि वर्तमान मामले में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी. गुणशेखरन (उल्लेखित)**; **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन बनाम स्मिता शरद देशमुख एवं अन्य (उल्लेखित)** तथा **सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एवं अन्य बनाम अबरार अली (उल्लेखित)** में स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के प्रशासनिक निर्णय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है।
28. तदनुसार, यह न्यायालय इस दृष्टिकोण का है कि उपर्युक्त उल्लेखित कारणों के मद्देनजर विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।
29. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31.07.2009 का विवादित आदेश निरस्त एवं समाप्त किया जाता है।
30. इसके परिणामस्वरूप, वेतन के अंतर की बकाया राशि, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
31. तदनुसार, यह रिट याचिका समाप्त की जाती है।
32. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, को भी समाप्त किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश)

सौरभ/-

ए.एफ.आर.

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**